डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 फरवरी, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 फरवरी, 2020

| वर्ष 63 | अंक 17 | भोपाल | 1 फरवरी, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

गणतंत्र दिवस समारोह में जय किसान फसल ऋण माफी योजना पर आधारित सहकारिता विभाग की झांकी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रदर्शित

भोपाल। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की नई सोच–नया मध्यप्रदेश थीम पर बनाई गयी झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सहकारिता विभाग की झांकी का म.प्र. राज्य सहकारी संघ ने प्रदर्शन किया जिसकी मुख्य थीम थी– "जय किसान फसल ऋण माफी योजना"।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्रदेश के किसान की ऋण ग्रस्तता के निवारण के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना लागू की गयी है। योजना में 31.3.2018 पर जिन किसानों पर राशि रू. 2.00 लाख तक का ऋण शेष है वह इसके लिये पात्र है। सहकारी समितियों के 8.53 लाख पीए लोन कृषकों के राशि रू. 2068 करोड़ एवं 9.43 लाख एनपीए लोन कृषकों के राशि रू. 4800 करोड़ की ऋण माफी की गई है। अभी तक सहकारी समितियों के कुल 17.96 लाख किसानों के राशि रू.6868 करोड़ से अधिक की ऋणमाफी की जा चुकी है।

उक्त ऋण माफी के फलस्वरूप 9.43 लाख एनपीए लोन की श्रेणी वाले कृषक शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर नये फसल ऋण लेने के लिये पात्र हो गये है। इन कालातीत कृषकों में से खरीफ 2019 में 4.84 लाख कृषकों को राशि रू.1607 करोड़ एवं रबी 2019–20 सीजन में 2.48 लाख कृषकों को राशि रू.561 करोड़ का फसल ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2019–20 में खरीफ 2019 में राशि रू. 7752.29 करोड़ एवं रबी 2019–20 में राशि रु. 2467.22 करोड़ कुल राशि रु. 10219.51 करोड़ का फसल ऋण वितरण दिनांक 10.01.2020 तक कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है। ऋण माफी के द्वितीय चरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गयी है।

ऋण माफी की राशि प्राप्त होने से 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंके, नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्ति हेतु पात्र हो गये, 11 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा विपणन संघ के खाद की बकाया राशि का भुगतान किया गया एवं 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा अपेक्स बैंक की कालातीत राशि की अदायगी की गई।

अपेक्स बैंक प्रशासक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के प्रशासक श्री अशोक सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ परिसर में प्रबंध संचालक श्री रंजन ने किया ध्वजारोहण

भोपाल। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने राज्य सहकारी संघ परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर राज्य सहकारी संघ के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लें प्रदेशवासी

राज्यपाल श्री टंडन द्वारा राज्य–स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण

भोपाल। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने 71वें गणतंत्र दिवस पर लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य–स्तरीय समारोह में प्रदेशवासियों का आव्हान किया है कि प्रदेश में गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयासों में राज्य सरकार का सहयोग करें। श्री टंडन ने समारोह में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। श्री टंडन ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और संविधान सभा के सदस्यों का पुण्य स्मरण किया।

राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि युवाओं को भविष्योन्मुखी और रोज़गारपरक शिक्षण के लिए प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। संभागीय मुख्यालयों के आई.टी.आई. संस्थानों को मेगा आई.टी.आई. में उन्नत किया जा रहा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक नल–जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेय जल आपूर्ति के कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख आवासहीन परिवारों के लिए आवास की आवश्यक अधोसंरचना का भी विकास किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आवास मिशन के आवासहीनों को किराए पर मकान मिलेंगे, जिनका 15 साल तक किराया देने के बाद मकान हितग्राही का हो जाएगा। राज्यपाल ने बताया कि गौवंश को आश्रय देने के लिए प्रदेश में एक हजार गौशालाएँ बनाई जा रही हैं। प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ के चारागाह भी विकसित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि

गौ–शाला के लिए चारा–भूसा का दैनिक अनुदान तीन रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये प्रति गौवंश किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिये वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावों पर समयबद्धता के साथ पुनर्विचार किया जा रहा है। एक माह में ऐसे सभी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा। तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी दर में वृद्धि कर इसे दो हजार से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और आदिवासियों के विकास पर जनसंख्या के मान से ही उचित बजट का आवंटन होगा।

राज्यपाल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण को मंजूरी दी गई है। लोगों को रोज़गार के अवसर मिलें, इसके लिए प्रदेश को विश्व–स्तरीय पर्यटन स्थल की पहचान दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

गणतंत्र दिवस के राज्य–स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में जन–प्रतिनिधि,गणमान्य नागरिक, शासकीय अधिकारी–कर्मचारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए।

किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर पर भी मिलेगा अनुदान

भोपाल। राज्य सरकार ने इस वर्ष से किसानों को कम्बाइन हॉर्वेस्टर खरीदने पर भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाली अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है। अब लघु, सीमांत, अनुसूचित– जाति, अनुसूचित– जनजाति तथा महिला कृषकों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर कीमत का 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को कीमत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

भण्डारित अनाज पर ऋण

प्रदेश में किसानों को आत्म–निर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने भण्डार–गृहों में भण्डारित अनाज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है। किसान को उसकी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलने तक भण्डार–गृहों में उपज रखने की सुविधा दी गई है। एक फसल मौसम तक भण्डार– गृह में कृषि उपज रखने का शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।

पौने चार हजार क्लस्टर में जैविक खेती

राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये करीब पौने चार हजार क्लस्टर/समूह में जैविक खेती का कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये किसानों को खेत की मिट्टी और उनके द्वारा तैयार बीज के मुफ्त परीक्षण की सुविधा दी गई है। प्रदेश में पिछले एक साल में अभियान चलाकर किसानों को 58 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ–कार्ड प्रदाय किये गये हैं।

मुख्यमंत्री बागवानी–खाद्य प्र–संस्करण योजना

प्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्र–संस्करण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में औद्योगिक/ शासकीय भूमि पर क्लस्टर विकसित कर पॉली–हाउस/शेडनेट–हाउस के अंदर फूलों और मसालों की खेती, टिश्यू कल्चर लैब और हाईटेक नर्सरी का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में किया ध्वजारोहण

आकर्षक परेड के साथ हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम

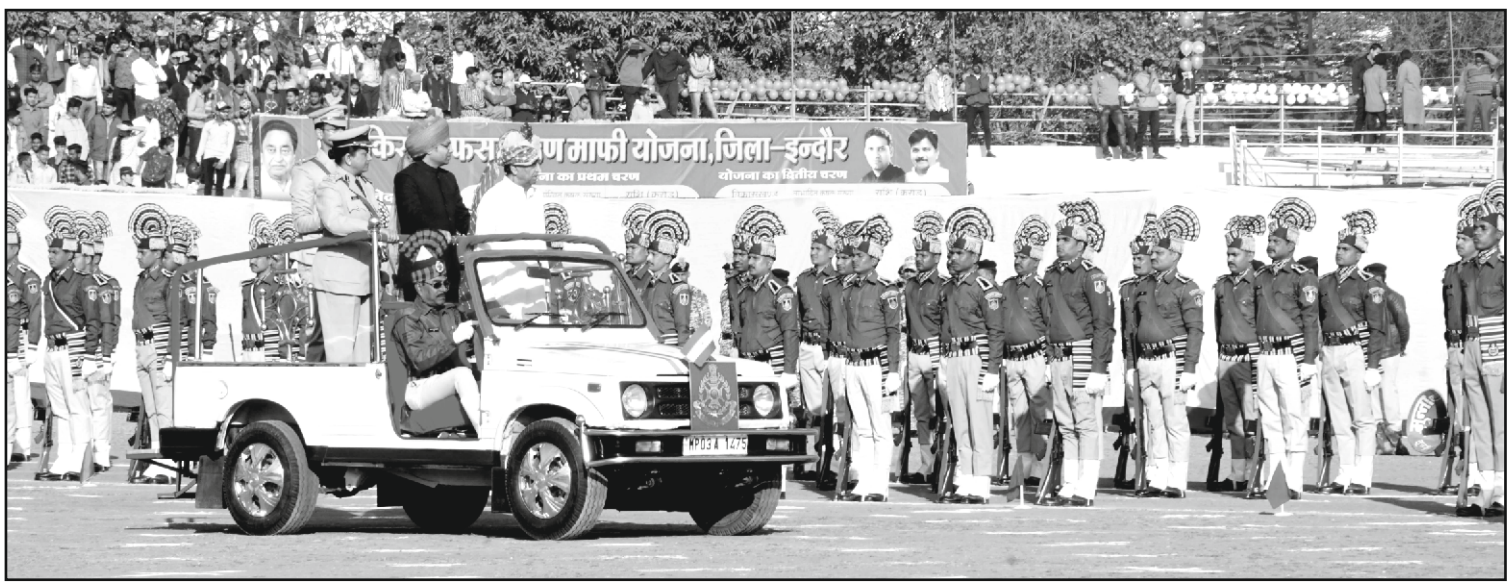

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। सम्पूर्ण गरिमा, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा नयनाभिराम झांकियां भी निकाली गयी। समारोह में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश की जनता को सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश के प्रमुख बिन्दु

- जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्य को मिलने वाली राशि में कमी।
- गांधीजी की भावना के अनुरूप विजन–टू–डिलीवरी रोडमैप
- एक साल में लगभग 20 लाख किसानों के ऋण माफ।
- रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण और रुपये 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ। दूसरा चरण शुरू। एक लाख तक के चालू फसल ऋण और रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण माफी के लिये बचे पात्र किसानों की ऋण माफी होगी।
- भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना 'भविष्य'।
- नए उद्योगों में युवाओं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार को अनिवार्य।
- उद्योग चलाना आसान करने एक नया कानून। सभी तरह की अनुमतियाँ अधिकतम सात दिन में।
- संभागीय मुख्यालयों में स्थित आईटीआई संस्थानों का मेगा आईटीआई में उन्नयन।
- प्रत्येक गाँव में सड़क, बिजली और ब्राडबैंड यानि इंटरनेट सुविधा ।
- 40 लाख आवासहीन परिवार को आवास की व्यवस्था।
- पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम प्रारंभ।
- गौशाला को चारा– भूसा के लिये रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश।
- अनुसूचित जनजाति प्लान बनाने की प्रथा को केन्द्र ने खत्म कर दिया। भारत सरकार से चर्चा कर इसे पुनरू लागू किया जाए।
- स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये करीब 21 हजार शिक्षकों की भर्ती।
- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षाविदों की परिषद का गठन।
- कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना।
- नागरिकों को घर पहुँच सरकारी सेवाएं देने की शुरूआत इंदौर शहर से।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने साकार किया 767 जरूरतमंदों के घर का सपना

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को सौंपे गये भूखण्ड के कब्जा प्रमाण–पत्र

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिले में संचालित ऑपरेशन क्लीन अभियान में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के लाभान्वित सदस्यों को आवासीय भूखण्ड के कब्जा–पत्र सौंपे। अभियान के प्रथम चरण में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के 767 सदस्यों को लाभान्वित किया गया। इससे गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं से परेशान सदस्यों का अपने आशियाने का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप सात संस्थाओं के पाँच–पाँच सदस्यों को भूखण्ड आवंटन–पत्र एवं कब्जा–पत्र सौंपे। अभियान के द्वितीय चरण में 31 मार्च 2020 तक लगभग दो हजार पात्र सदस्यों को भूखंड/ प्रकोष्ठ प्रदाय जायेगा।

इंदौर जिले में इस अभियान में पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं में से लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 31 सदस्यों को 31 भूखंड, सुविधा गृह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 17 सदस्यों को 17 भूखंड, कसेरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 58 सदस्यों को 58 भूखंड, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 50 सदस्यों को 50 भूखंड, आस्था गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 50 सदस्यों को 50 भूखंड, रूपरेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 536 सदस्यों को 536 भूखंड, महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के 23 सदस्यों को 23 भूखंड के आवंटन पत्र तथा कब्जा पत्र प्रदान किये गये।

लाभान्वित सदस्यों ने जाहिर की खुशियाँ

कार्यक्रम में लाभान्वित सदस्य अपने आशियाने का सपना साकार होने से बेहद खुश दिखायी दिये। लाभान्वित सदस्य राजेन्द्र कुमार, रामकुमार, चन्द्रशेखर, निशा गर्ग आदि का कहना था कि बरसों से भटक रहे हम सदस्यों को अब न्याय मिला है। इसके लिये शासन और प्रशासन बधाई के पात्र हैं। भू–माफिया के विरूद्ध मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर चलाये गये अभियान के परिणामस्वरूप आज हमें अपना हक मिला।

सहकारिता माफिया के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए : सहकारिता मंत्री

सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर सहकारी बैंक के प्रशासक नियुक्त

ग्वालियर। सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सहकारिता माफिया के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। विशेषकर सहकारी गृह निर्माण समितियों के ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने सदस्यों से रूपए लेने के बाद भी प्लॉट नहीं दिए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इस अवसर पर उन्होंने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में डिपोजिट बढ़ाने के भी निर्देश दिए। डॉ. गोविंद सिंह ने यह निर्देश यहां मोतीमहल के मानसभागार में आयोजित ग्वालियर एवं चंबल संभागों की सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने जिला पंचायत ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त करने की घोषणा भी की।

बैठक में सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री एम के अग्रवाल, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, एपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक तथा सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिए कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया जाए। जिसमें संस्थाओं की जमीन अवश्य देखी जाएं। इसके अलावा कितने सदस्यों को प्लॉट मिल गए हैं एवं कितने शेष हैं, यह भी देखा जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी संस्था का कोई विवाद है तो उसका निराकरण कराकर सदस्यों को प्लाट दिए जाएं। इसके लिए सहकारिता विभाग, नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संस्थायें समन्वय से कार्य करें। डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिए कि संस्था में हुए विकास के नाम पर फर्जी खर्च की जांच की जाए। उन्होंने गृह निर्माण समितियों का शतप्रतिशत ऑडिट करने के भी निर्देश दिए। ऑडिट में विशेषकर पिछले वर्षों के ऑडिट नोट देखने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिए कि जिन संस्थाओं के पदाधिकारी ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ लिखकर दें एवं एफआईआर दर्ज कराएं। साथ ही उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि 24 संस्थाओं की 26 नस्तियां गायब हैं। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन संस्थाओं का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनका बोर्ड भंग करें। साथ ही समाचार पत्रों में ऐसी संस्थाओं का नाम प्रकाशित कराया जाए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि संस्थाओं के गलत कार्य में विभाग के जो अधिकारी एवं कर्मचारी संलग्न हैं उनकी गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टीप लिखी जाए, वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाए एवं पदावनत करने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कार्य में सुधार नहीं होता है तो 20–50 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए।

उपायुक्त सहकारिता ग्वालियर बैठक से अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर निर्देश दिए कि 25 जनवरी की शाम तक यदि वे मुख्यालय पर नहीं आते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि सात दिन बाद फिर समीक्षा की जायेगी। इसलिए बैठक में अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। ग्वालियर एवं चंबल संभागों की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की समीक्षा करते हुए सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि बैंकों का डिपोजिट बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों के सहकारी बैंकों में खाते खुलवाये जायें। बैंक कर्मचारीवार एवं सोसायटीवार मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। जो कर्मचारी लक्ष्य पूरा नहीं करें, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए और जो अच्छा कार्य करें उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए जाएं। उन्होंने बैंकों के जनरल मैनेजरों को निर्देश दिए कि ऋण वितरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऋण माफी की निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अकृषि ऋणों की वसूली की जाए। उन्होंने दतिया के बैंक महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह में कार्य में सुधार लाएं अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशास–नात्मक कार्रवाई की जायेगी।

कड़नाथ मुर्गी पालन के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करें : मंत्री श्री यादव

भोपाल। पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने बानमोर में सहकारी दुग्ध संघ मुरैना द्वारा संचालित दुग्ध संयंत्र एवं रायरू में शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कड़कनाथ और आरआईआर प्रजाति की मुर्गियों के चूजे पालकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन प्रजातियों के मुर्गी–पालन के लिये हितग्राहियों को प्रोत्साहित करें।

मंत्री श्री यादव ने प्रक्षेत्र में कड़कनाथ, आरआईआर और चेपब्रो प्रजाति के मुर्गी पालन के साथ इन प्रजातियों की मुर्गियों के अंडों से विशेष मशीन द्वारा 21 दिन में चूजे निकलने की प्रक्रिया को देखा। इस प्रक्रिया में 18 दिन तक अंडों को मशीन में रखकर निर्धारित तापमान दिया जाता है। इसके बाद तीन दिन हेचर होने पर मुर्गी का चूजा प्राप्त होता है। चूजों को अनुकूल वातावरण देकर उनकी देख–रेख की जाती है। शासकीय कुक्कुट–पालन प्रक्षेत्र रायरू में 6–7 हजार मुर्गे एवं मुर्गियां हैं। यहाँ तैयार चूजे ग्वालियर एवं चंबल संभाग में सप्लाई किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री ने प्रक्षेत्र की गतिविधियों की सराहना की।

पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने बानमोर में अधिकारियों को दुग्ध संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने दूध की पैकिंग, पाउडर प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल लैब, कलेक्शन डॉक और आरएसआरडी का अवलोकन किया।

बुजुर्ग, दिव्यांग तथा बीमार उपभोक्ताओं के लिए राशन की दुकानों पर होगी विशेष व्यवस्था

भोपाल। खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर बेहतर गुणवत्ता की खाद्य सामग्री सहज रूप से उपलब्ध करायी जाये। राशन की दुकानों पर आने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग तथा बीमार उपभोक्ताओं को राशन के लिये कतार में खड़ा नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उपभोक्ताओं के हितों के साथ लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी और दुकानदार को बख्शा नहीं जायेगा। मंत्री श्री सिंह तोमर ने इंदौर में संभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी विशेष रूप से शामिल हुए।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खाद्य विभाग जरूरतमंद व्यक्तियों के हितों का रक्षक है। सभी अधिकारी मानवीयता एवं सेवा भाव से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें। श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यह प्रयास किये जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को सहज रूप से खाद्यान्न सामग्री मिले। ऐसे उपभोक्ता जो राशन की दुकान तक नहीं आ सकते हैं, उन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा जिलों में अग्रिम आवंटन दिया जा रहा है, जिससे दुकानदार अग्रिम उठाव कर अगले माह की पहली तारीख से ही खाद्यान्न वितरण शुरू कर सके। अभी से ही फरवरी माह का आवंटन जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन के लिये सभी खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये छाया, पानी, भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाये। किसानों को समय पर उनकी उपज का भुगतान भी मिले। श्री तोमर ने पेट्रोल पम्पों की नियमित जाँच करने के निर्देश दिए।

कृषि उत्पादन और कृषकों की आय बढ़ाने का उपाय करें

संभागायुक्त द्वारा कृषि की समीक्षा

जबलपुर। संभाग में रबी फसलों की 93 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। लक्ष्य 18 लाख 74 हजार हेक्टेयर के विरूद्ध अब तक 17 लाख 49 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र रबी फसलों से आच्छादित हुआ है। गत वर्ष 16 लाख 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी फसलों से आच्छादित हुआ था।

यह जानकारी संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, दुग्ध संघ और मछली पालन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में मिली।

संभागायुक्त श्री मिश्रा ने कहा हर कृषि क्षेत्र में कम से कम 3 से 4 फसलें कृषकों द्वारा ली जाय। कृषि से उद्यानिकी को जोड़कर विभिन्न प्रकार की सब्जियों तथा आय देने वाली उद्यानिकी फसलों का उत्पादन लेने कृषकों को प्रेरित किया जाय। उद्यानिकी उत्पादों के लिये मुख्य सड़क किनारे विण्डो शॉपिंग क्षेत्र विकसित किये जायं या बिक्री के लिये उपलब्ध फलों की जानकारी देने वाले पोस्टर लगाये जायं।

सहकारिता विभाग के योजनाओं की समीक्षा में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी फसल बीमा की प्रिमियम राशि के भुगतान से लेकर फसल का नुकसान होने पर बीमा राशि किसान को मिलने तक मॉनीटरिंग करें। बीमा राशि भुगतान से संबंधित किसी समस्या पर सहकारिता, बीमा कंपनी और बैंक अधिकारी संयुक्त रूप से निराकरण करें। उन्होंने सहकारी बैंकों के लिये ऋण वसूली की ओर भी ध्यान देने कहा। सहकारी समितियों और सचिवों के कामकाज पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये।

राज्य सरकार ने शुरू किया आम आदमी के सर्वांगीण विकास का सिलसिला

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने प्रभार के जिला रायसेन में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार ने पिछले एक वर्ष में सभी वर्गो के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों का अपना घर का सपना साकार करने के लिये सरकार ने कलेक्टर गाईड लाईन में जमीन के दामों में 20 प्रतिशत की कमी की। आवास मिशन में प्रति परिवार दो लाख 50 हजार रूपये सहायता देना शुरू किया। भूमिहीनों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए गये। इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू कर कमजोर वर्ग को हजारों रूपए के बिजली बिल से मुक्ति दिलाई गई। उन्होंने कहा कि कहा कि अब प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रूपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही है। साथ ही, किसानों को 10 हार्स पॉवर तक के पम्पों के लिए आधी दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रभारी मंत्री श्री यादव ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों का दो लाख रूपए तक का फसल ऋण माफ किया। पहले चरण में 20 लाख से अधिक किसानों का फसल ऋण माफ किया गया। शेष पात्र किसानों का फसल ऋण माफ करने के लिए दूसरा चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पांचवी और आठवीं कक्षा को पुनः बोर्ड परीक्षा में शामिल किया गया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 35 हजार से अधिक शिक्षकों का ऑनलाईन ट्रांसफर किया गया।

मंत्री श्री यादव ने लोगों को बताया कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 600 रूपए प्रतिमाह कर बुजुर्गों को राहत दी है। कन्या विवाह/निकाह योजना में सहायता राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई। महिलाओं और युवतियों को निःशुल्क ड्राईविंग लायसेंस देने का सिलसिला शुरू किया गया। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत नौकरियाँ स्थानीय लोगों को देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

सहिष्णुता की संस्कृति है भारत की पहचान : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा प्रदेश है, जो विविधताओं से सम्पन्न है और पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है, जो विविधताओं से पूर्ण है। इस विविधता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि विविधता में भारत की बराबरी करने वाला देश सिर्फ सोवियत संघ था। आज वह अस्तित्व में नहीं है क्योंकि उसमें भारत जैसी सोच–समझ और सहिष्णुता की संस्कृति नहीं थी। यही भारत की पहचान है। मुख्यमंत्री आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आईएएस सर्विस मीट 2020 के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

न्याय की कोई सीमा नहीं

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि जो आईएएस अधिकारी अपनी सेवा यात्रा के मध्य में हैं और जो सेवा पूरी करने वाले हैं, वे चिंतन करें कि मध्यप्रदेश को वे कहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। जो अधिकारी अपनी सेवा यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं, वे सोचें कि मध्यप्रदेश को कहाँ देखना चाहते हैं।

श्री कमल नाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय देने वाला बताते हुए कहा कि संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों की सीमाएँ हो सकती हैं लेकिन न्याय की कोई सीमा नहीं है। यह हर समय और परिस्थिति में दिया जा सकता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जो क्षमता और कौशल है, वह सामान्यतरू राजनैतिक नेतृत्व के पास नहीं रहता। राजनैतिक नेतृत्व बदलते ही प्रशासनिक तंत्र का भी नया जन्म होता है लेकिन ज्ञान, कला, कौशल नहीं बदलते।

न्यू आइडिया आफ चेंज के लिए तीन पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने नए परिवर्तन–कारी विचारों (न्यू आइडिया आफ चेंज) के लिए तीन पुरस्कार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिवों की एक ज्यूरी बनाई जाएगी, जो सर्वोत्कृष्ट आईडिया चुनेगी।

बदलनी होगी प्रदेश की वर्तमान प्रोफाईल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य की अपना प्रोफाईल होती है। सबको मिलकर मध्यप्रदेश का प्रोफाईल बनाना होगा। वर्तमान प्रोफाईल को बदलना होगा। मध्यप्रदेश की नई पहचान बनानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियाँ उत्पन्न हों।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हर पल बदल रही है। पूरा भारत बदल रहा है। ज्ञान और सूचना के भंडार तक आज जो पहुँच बढ़ी है, वह पहले नहीं थी। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी जनसंख्या भारत में है। ये जनसंख्या युवाओं की है। बदलते समय में महत्वाकांक्षाएँ भी बदल रही हैं। अब यह देखना है कि इन्हें कैसे अपनाएं।

वर्तमान में अधिक उत्पादन चुनौती

श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित अर्थ–व्यवस्था का प्रदेश है। वर्तमान समय में अधिक उत्पादन की चुनौती है। खाद्यान्न की कमी अब चुनौती नहीं रही। उन्होंने कहा कि परिवर्तन तब दिखेगा, जब धोती–पायजामा पहनने वाला किसान आधुनिक खेती करते हुए जींस और शर्ट वाला किसान बन जाये।

कौशल सम्पन्न युवाओं को रोजगार की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारी नई पीढ़ी की है। उन्होंने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में कौशल सम्पन्न युवा तैयार होते हैं। उन्हें रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोजगार आर्थिक गतिविधियों का एक घटक है। इसलिए आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाना चुनौतीपूर्ण काम है। उन्होंने कहा कि हर सरकार की अपनी कार्य–शैली होती है। अपनी अच्छाईयाँ और कमजोरियाँ होती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की नई पीढ़ी को यह देखना होगा कि मध्यप्रदेश को किस दिशा में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक आर्थिक शक्ति बनने की संभावना रखता है। मध्यप्रदेश के पास लॉजिस्टिक लाभ है। यहाँ का बाजार और व्यापार पूरे देश से जुड़ सकता है। सिर्फ नजरिए में परिवर्तन लाने की देर है। इसके लिए नया सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या सीखते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे सीखते हैं।

मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने आईएएस मीट के आयोजन की पृष्ठभूमि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नई ऊर्जा और अनुभव को एक साथ लाने का अवसर है ताकि यह कार्य–शैली में भी बना रहे और इसका भरपूर लाभ समाज को मिले।

अपर मुख्य सचिव सर्वश्री एम. गोपाल रेड्डी, श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने अतिथियों को स्मृति–चिन्ह भेंट किये।

प्रारंभ में मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आई. सी.पी. केशरी ने अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री को आधुनिक, उदार, डॉयनामिक और विश्व–दृष्टि से सम्पन्न नेता बताते हुए कहा कि वे 159 देशों का भ्रमण कर चुके हैं । वे किसानों के हित में 19 मंत्रियों के साथ विश्व व्यापार संगठन की बैठक का विरोध करने वाले नेता हैं। उनके नेतृत्व में देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रख्यात लेखक श्री पवन वर्मा और प्रशासन अकादमी की महानिदेशक सुश्री वीरा राणा उपस्थित थी।

स्व-सहायता समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलेगा : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि स्व–सहायता समूहों को राज्य सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज पर 30 हजार रूपये तक का ऋण मुहैया कराएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक् से एक फंड बनाया जा रहा है। उन्होंने यह बात भोपाल हाट बाजार में आयोजित रीजनल सरस मेले के उद्घाटन समारोह में कही। सरस मेले का आयोजन 15 जनवरी से 27 जनवरी 2020 तक किया जाएगा। इस मेले में 15 राज्यों के 194 स्व–सहायता समूह अपने उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक साधन मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले शिल्पियों को सरस मेले के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शिल्प मेलों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं को समूह के रूप में संगठित कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। समूहों को बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से आसान किस्तों पर ऋण मुहैया कराने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सामग्री से बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मुहैया कराने का प्रयास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किशोर बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करेगी 'उमंग' हेल्पलाइन

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी द्वारा हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र का शुभारंभ

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425 एवं परामर्श केन्द्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे किशोर बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि परामर्श केन्द्रों में बच्चों की पहचान को गुप्त रखा जायेगा, ताकि वे निडर होकर अपनी बात कह सकें।

मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि किशोर बच्चों को अज्ञानतावश गलत कदम उठाने से रोकने के लिये यह हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र स्थापित कर राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित किया है। 'उमंग' हेल्पलाइन 14425 निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि एक राज्य–स्तरीय सहित 313 विकासखण्डों पर परामर्श केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर एक ही समय में 16 से 20 कॉल अटेंड किये जायेंगे। परामर्श केन्द्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेंगे। प्रत्येक केन्द्र में दो परामर्शदाताओं के हिसाब से कुल 626 परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। यह केन्द्र 9228 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के बच्चों को परामर्श देंगे।

38 लाख से अधिक किशोर–किशोरी और अभिभावक होंगे लाभान्वित

प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने बताया कि स्वास्थ्य, महिला–बाल विकास, पुलिस और न्याय विभाग के सहयोग से 'उमंग' हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र 38 लाख से भी अधिक किशोर बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे।

आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताये गये 10 जीवन–कौशल को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र का मॉड्यूल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यूएनएफटीए, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर और आरईसी फाउण्डेशन के सहयोग से ष्उमंगश्श हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी किशोर बालक–बालिकाओं के लिये अलग–अलग मार्गदर्शिका बनाई गई है।

मार्गदर्शिका, फ्लिप बुक और सफलता की कहानियों का विमोचन

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी ने इस अवसर पर उमंग परामर्श कौशल प्रशिक्षण मार्गदर्शिका और फ्लिप बुक तथा कक्षा 12वीं के किशोर–किशोरियों के लिये सफलता की कहानियों का विमोचन किया। यूएनएफपीए इंडिया नई दिल्ली की प्रतिनिधि सुश्री अंर्जेटीना माटावेल पिक्किन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

परामर्श केन्द्र की विशेषता

यू.एन.एफ.पी.ए. (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) के राज्य कार्यक्रम समन्वयक डॉ. निलेश देशपाण्डे ने पी.पी.टी. के माध्यम से बताया कि ''उमंग'' किशोर हेल्पलाइन एवं परामर्श केन्द्रों में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसमें लैंड–लाइन नंबर को मेप किया जाता है। डाटा से संबंधित सूचनाओं को रिकॉर्ड करके मासिक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। क्लांइट के साथ लाइव चेट की जा सकेगी तथा ईमेल द्वारा भी परामर्श दिया जा सकेगा। परामर्शदाता ने कितने कॉल अटेंड किये तथा कितना समय लिया यह भी रिकॉर्ड रहेगा। प्रत्येक कॉलर की उम्र, लिंग, स्थान, कॉल का प्रकार आदि का भी रिकॉर्ड रहेगा।

विशेषज्ञ परामर्शदाता

विकासखण्ड स्तरीय परामर्श केन्द्रों में एक महिला एवं एक पुरूष परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है, जिनका विशेषज्ञों द्वारा साईकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया है। परामर्शदाताओं को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुम्बई में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया। साथ ही, विषय–विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

सभी परामर्शदाताओं को प्रत्येक 6 माह में प्रशिक्षण दिया जायेगा। साप्ताहिक मॉक सेशंस भी होंगे। कार्यस्थल पर परामर्शदाताओं के लिए भी साईको थेरेपी एवं रिलेक्सेशन जोन का प्रावधान किया गया है फोन कॉल पर बात करने की कोई सीमा नहीं है। परामर्शदाता मानसिक एवं शारीरिक बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य, नशे की लत, गैर–संचारी रोग, भावनात्मक समस्या, पोषण, शैक्षणिक एवं करियर परामर्श, आपसी रिश्ते एवं आत्महत्या की रोकथाम आदि पर परामर्श देंगे।

नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए

भोपाल। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव की उपस्थिति में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (रम्स) के बीच मंत्रालय में आगर, शाजापुर और नीमच में कुल 1500 मेगावाट सौर पार्कों के ए आंतरिक ग्रिड संयोजन के लिए सब–स्टेशन एवं लाईन निर्माण के लिए अनुबंध किया गया। इस अवसर पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) को परियोजना सलाहकार सेवा प्रदान करने के लिए सलाहकार नियुक्त करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की ओर से श्री राजीव रंजन मीणा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रम्स तथा श्री टी.सी. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मंत्री श्री हर्ष यादव ने इस अवसर पर रम्स के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आगर, शाजापुर और नीमच सौर पार्क भी पूर्व में निष्पादित रीवा परियोजना की तरह इतिहास रचेंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट के आगामी सौर पार्कों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का प्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा सम्पन्न राज्यों में अग्रणी बनाने में प्रमुख कदम होगा। श्री राजीव रंजन मीणा ने विश्वास जताया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से परियोजना नियत समय में पूर्ण होगी।

सुरक्षित भविष्य के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण आवश्यक : मंत्री श्री तोमर

भोपाल। खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पेट्रोलियम पदार्थो का संरक्षण आवश्यक है। श्री तोमर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'संरक्षण क्षमता महोत्सव' को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। प्रकृति के अन्य स्त्रोतों की तरह इसकी उपलब्धता भी सीमित है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों कि लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पेट्रोलियम उत्पादों के बिना जीवन कैसा होगा, यह सोचना भी कठिन है। देश–विदेश के वैज्ञानिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को तलाशने में जुटे हैं। उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है लेकिन ईंधन के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का पूर्ण विकल्प मिलना आसान नहीं दिखता।

खाद्य–नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ईंधन की बचत करके ही हम इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते है। श्री तोमर ने उपस्थित जन–समुदाय को ईधन बचाने की शपथ दिलाई।

पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आगामी 15 फरवरी तक यह महोत्सव पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है।

प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस

भोपाल। मध्यप्रदेश में 71वाँ गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए समारोह में प्रदेश के मंत्रियों ने ध्वजारोहण करने के साथ परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के संदेश का वाचन किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय कर्मियों तथा विकास झाँकियों को पुरस्कृत किया गया। छात्र–छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और विभागों की शासकीय योजनाओं पर केन्द्रित आकर्षक झाँकियों ने लोगों का मन मोह लिया। जिलों में मंत्री और कलेक्टर ने समारोह के बाद शासकीय स्कूलों के बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन किया।

भिण्ड : सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने भिण्ड के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, अधिकारियों–कर्मचारियों और प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया। मध्यान्ह भोजन के बाद डॉ. सिंह ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं को साइकिल वितरण किया।

सीहोर : गैस त्रासदी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील ने सीहोर के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के साथ परेड की सलामी ली। श्री अकील ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 69 अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान करने के साथ शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों का लोकार्पण कर हितग्राहियों को पट्टे प्रदान किये।

धार : वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने धार जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। श्री सिंघार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री तोमर की पत्नी श्रीमती कमला देवी को सम्मानित किया। वन मंत्री ने समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों तथा प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रशंसा–पत्र देकर सम्मानित किया।

रीवा : सामाजिक न्याय एवं अनुसूचित–जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने रीवा जिले के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया। सैनिक स्कूल के बच्चों ने मधुर धुन के साथ योगाभ्यास की प्रस्तुति दी। वहीं अन्य स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों ने वन्दे मातरम गीत के साथ सामूहिक व्यायाम प्रदर्शित किया।

श्योपुर : पशुपालन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने श्योपुर जिला मुख्यालय में हुए मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी–कर्मचारी, विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया।

ग्वालियर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। दर्शकों ने समारोह में हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड के प्रदर्शन को काफी सराहा। स्कूली बच्चों ने जाँबाज सैनिकों की गाथा प्रस्तुत कर दर्शकों को देशभक्ति के जज़्बे से सराबोर कर दिया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय स्वान दस्ते द्वारा किये गये हैरतअंगेज कर्त्तव्यों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

जबलपुर : वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरुण भनोत ने पं. रविशंकर शुक्ल खेल परिसर में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। वुशू मार्शल ऑर्ट की महिला खिलाड़ियों ने प्रभावी प्रस्तुति देकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इन खिलाड़ियों ने एक हजार से अधिक पुरस्कार प्राप्त किये हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 7 बार ख्याति बटोर चुके अहीर नृत्य की प्रस्तुति ने भी लोगों का मन मोहा।

डिण्डोरी : आदिम–जाति, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध–घुमक्कड़ कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने पुलिस परेड ग्राउण्ड पर हुए मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग, अधिकारियों, खिलाड़ियों और छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया।

बड़वानी : गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। श्री बच्चन ने शहीदों के परिजनों का सम्मान करने के साथ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ आदिवासी लोक–नृत्य भी किया। गृह मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ नवाचार करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया।

छिन्दवाड़ा : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने छिन्दवाड़ा के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी–कर्मचारियों और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया।

गुना : श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने गुना के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। गुना के 750 छात्र–छात्राओं ने एक धुन प सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन ''व्यायाम करें स्वस्थ रहें'' का संदेश दिया।

मुरैना में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास, दतिया में कलेक्टर श्री रोहित सिंह, झाबुआ में कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा, शहडोल में कलेक्टर श्री ललित दाहिमा ने गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में ध्वजारोहण

इंदौर। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में प्र. प्राचार्य एन.के. कसारा ने केन्द्र परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर केन्द्र के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में ध्वजारोहण

जबलपुर। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में प्राचार्य यशोवर्धन पाठक ने केन्द्र परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर केन्द्र के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

नव नियुक्त उप अंकेक्षकों हेतु अंकेक्षण प्रणाली एवं विभागीय कर्तव्य तथा दायित्व निर्वहन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में सहकारिता विभाग के जिलों/मुख्यालय में पदस्थ नव नियुक्त उप अंकेक्षको हेतु अंकेक्षण प्रणाली एवं विभागीय कर्तव्य तथा दायित्व निर्वहन पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 25 उप अंकेक्षको ने भाग लिया। उप अंकेक्षको को सहकारिता, सहकारिता विभाग के प्रमुख कार्य पद्धति सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधान, वित्तीय लेखांकन, शिकायतों की जांच, गबन, ई–कॉपरेटिव्ह तथा सूचना के अधिकार अधिनियम पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

वसूली, बिक्री अधिकारियों एवं परिसमापकों का प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में माह दिसंबर एवं जनवरी 2020 के दौरान वसूली, बिक्री अधिकारियों एवं परिसमापकों हेतु तीन तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के कुल 4 सत्रों का आयोजन किया गया। प्रत्येक सत्र में कुल दो संभागों के प्रत्येक जिले में कार्यरत वसूली अधिकारियों एवं परिसमापकों तथा बिक्री अधिकारियों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग के कुल 74 सहकारी निरीक्षकों, उप अंकेक्षकों, अंकेक्षण अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षकों, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों, अंकेक्षकों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत, न पटाए गए कृषि ऋणों, गैर कृषि ऋणों की, नियमानुसार अधिरोपित विभिन्न शास्तियों की वसूली हेतु वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार ऐसी सहकारी समितियां जो अपने निर्धारित उददेश्य को पूर्ण कर चुकीं हैं, अथवा उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहीं हैं, इन समितियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर उनका परिसमापन किया जाता है। इन अधिकारियों को परिसमापक अधिकारी के दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है।

उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन में उपयोग आने वाले विभिन्न कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं ,प्रारूपों आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों जैसे– भू राजस्व संहिता अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियां, वसूली की प्रक्रिया, समन तथा नोटिस की तामीली, डिक्री एवं निष्पादन की कार्यवाही, परिसमापन के संबंध में अधिनियम , नियमों में प्रावधान, सम्पत्ति का मूल्यांकन, परिसमापन की प्रक्रिया, अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना एवं विघटन की कार्यवाही आदि पर विस्तृत जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। विषय विशेषज्ञों के रूप में श्री जे.पी. गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, श्री श्रीकुमार जोशी , सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, श्री डी.के. सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री भुवन गुप्ता, तहसीलदार, श्री पी. के.एस.परिहार ,सेवानिवृत्त प्रबंधक अपेक्स बैंक श्री संजय सिंह ,ओ. एस.डी. तथा श्रीमती रश्मि गोल्या , कारपोरेट ट्रेनर शामिल रहे। प्रशिक्षण के सत्रों का समन्वय केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री ए.के. जोशी के मार्गदर्शन में संघ की व्याख्याता श्रीमती रेखा पिप्पल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।